भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 508
23.07.2025 को उत्तर देने के लिए

कैलोरी और व्यय आधारित गरीबी रेखाएं

508. श्री सुदामा प्रसादः

क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को द इंडियन एक्सप्रेस में दिनांक 01/06/2025 को प्रकाशित उस रिपोर्ट की जानकारी है जिसमें बताया गया है कि कैलोरी/व्यय-आधारित गरीबी रेखाएँ व्यापक खाद्य अभाव को छिपाती हैं, क्योंकि 40 प्रतिशत ग्रामीण और 20-30 प्रतिशत शहरी परिवारों को प्रतिदिन दो समय का भोजन भी सुलभ नहीं हो पाता है;

(ख) गरीबी संकेतकों, जो स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे प्रमुख घरेलू व्ययों की उपेक्षा करते हैं, जो खाद्य उपभोग को कम करते हैं, पर निर्भर रहने के क्या कारण हैं और मौजूद वैकल्पिक विधि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने लक्षित कल्याणकारी योजनाओं के लिए वास्तविक अभाव की जाँच हेतु थाली आधारित उपभोग धारणा अपनाने पर विचार किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (एचसीईएस), 2023 की रिपोर्ट के बाद से अब तक वास्तविक खाद्य पहुँच और आहार की गुणवत्ता को शामिल करने हेतु गरीबी मापन में सुधार के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गरीबी में कमी सुनिश्चित करने के लिए गरीबी संबंधी आंकड़े एकत्र करने हेतु उत्तरदायी निकायों/समितियों का ब्यौरा क्या है और विगत दस वर्षों के दौरान गरीबी संबंधी राज्य-वार और जिला-वार आंकड़े क्या हैं?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), योजना मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा संस्कृति मंत्रालय राज्य मंत्री [राव इंद्रजीत सिंह]

(क) से (ङ): जी, हाँ । इंडियन एक्सप्रेस के दिनांक 01/06/2025 के अंक में ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है जो इस बात पर प्रकाश डालती हो कि कैलोरी/व्यय-आधारित गरीबी रेखाएं व्यापक खाद्य अभाव को छिपाती हैं, क्योंकि 40% ग्रामीण और 20-30% शहरी परिवार प्रतिदिन दो मूलभूत भोजन का खर्च नहीं उठा पाते हैं।

वर्ष 2021 में, भारत सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर जैसे आयामों में अतिव्यापी स्त्रोत कैप्चर करके गरीबी को मापने के लिए बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई) के रूप में जाना जाने वाला एक व्यापक सूचकांक तैयार किया है, जिसमें 12 संकेतक शामिल हैं। यह गरीबी में रहने वाले लोगों की भागीदारी और उनकी वंचितता की सीमा, दोनों को मापता है। इस सूचकांक का दूसरा संस्करण वर्ष 2023 में जारी किया गया था। नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय एमपीआई रिपोर्ट, 2023 के अनुसार, वर्ष 2015-16 और 2019-21 के बीच बहुआयामी गरीबी में जनसंख्या का अनुपात 24.85% से घटकर 14.96% हो गया, जो दर्शाता है कि इस अवधि के दौरान लगभग 135.5 मिलियन व्यक्ति गरीबी से बाहर आ गए हैं। इसके अतिरिक्त, नीति आयोग द्वारा 'भारत में 2005-06 से बहुआयामी गरीबी' पर प्रकाशित चर्चा पत्र के अनुसार, भारत में बहुआयामी गरीबी 2013-14 में 29.17% से घटकर 2022-23 में 11.28% होने का अनुमान है, जो दर्शाता है कि इस अवधि के दौरान 24.82 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आ गए हैं। यह सतत विकास लक्ष्य 1.2 को प्राप्त करने की दिशा में एक बड़ा योगदान है, जिसका उद्देश्य "राष्ट्रीय परिभाषाओं के अनुसार गरीबी के सभी आयामों में रहने वाले सभी आयु वर्ग के पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के अनुपात को कम से कम आधा करना" है। इससे संकेत मिलता है कि भारत 2030 से काफी पहले सतत विकास लक्ष्य 1.2 को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर है।

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (सां. और कार्य.कार्यां.मंत्रा.) के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने अगस्त, 2023-जुलाई, 2024 और अगस्त, 2022-जुलाई, 2023 के दौरान घरेलू उपभोग व्यय पर दो बैक-टू-बैक सर्वेक्षण किए, जिसमें शिक्षा, चिकित्सा आदि सहित लगभग 405 खाद्य और गैर-खाद्य वस्तुओं की घरेलू खपत की जानकारी एकत्र की गई है। एचसीईएस 2022-23 और एचसीईएस 2023-24 की रिपोर्ट क्रमशः जून 2024 और जनवरी 2025 में जारी की गई हैं।

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सर्वेक्षणों में सुदृढ़ एवं सुपरिभाषित कार्यविधियों का उपयोग किया जाता है, जिनमें बदलती आवश्यकताओं, फीडबैक और कार्यप्रणाली में प्रगति के आधार पर समय-समय पर सुधार किए जाते हैं, ताकि उनकी प्रभावशीलता बढ़ाई जा सके। आधिकारिक आंकड़ों की समीक्षा और सत्यापन के उद्देश्य से, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने समितियों/कार्य समूहों (डब्ल्यूजी) का गठन किया है, जिनमें केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, शिक्षा, अनुसंधान, अर्थशास्त्र, वित्त आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ सदस्य शामिल हैं।

*****